राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

विविध संदेश

वर्ष - 15 | अंक-79 | लखनऊ, 30 जनवरी ,शुक्रवार 2026 | पृष्ठ-04 | मूल्य-01 रुपए

एक नज़र

अजित पवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप वापस ले बीजेपी, यही होगी सच्ची श्रद्धांजलि : संजय राउत

एजेंसी

नवी मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. उनके निधन के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा है. राउत ने कहा कि बीजेपी ने पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े-बड़े अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाए हैं लेकिन इन विज्ञापनों से क्या होगा। राउत ने आगे कहा कि अगर बीजेपी सच में उन्हें सम्मान देना चाहती है, तो वह उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को वापस ले. तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी. राउत ने कहा कि अजित पवार को बीजेपी की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 70,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप वापस लें। भाजपा ने पहले उन पर सिंचाई विभाग में घोटाले का आरोप लगाया था. बीजेपी ने गुरुवार को प्रमुख समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर विज्ञापन छपवाकर पवार को श्रद्धांजलि दी. एक दिन पहले एक विमान दुर्घटना में पवार का निधन हो गया था।

यूजीसी नियमों पर सुप्रीम भेर्ट ने लगाई सुप्रीम ब्रेक

❖ कुल पांच लोगों की जान गई, हादसे के कारणों की जांच शुरु।

एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि नियमों की भाषा में स्पष्टता नहीं है. इसलिए इसकी जांच की जरूरत है, ताकि नियमों की भाषा सुधारी जाए, ताकि दुरुपयोग न किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेगुलेशन को फिर से बनाने को कहा, तब-तक 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे. अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यूजीसी के नये नियम के खिलाफ पूरे देश में बवाल मचा हुआ. गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने छात्रों के बीच भेदभाव के खिलाफ यूजीसी इक्विटी रूल्स के नए रेगुलेशंस पर एक पीआईएल पर सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने का आदेश दिया। सीजेआई ने कहा कि प्रथम दृष्टया हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट है, विशेषज्ञों को इसकी भाषा को संशोधित करने के लिए जांच करने की आवश्यकता है ताकि इसका दुरुपयोग न हो। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि इस न्यायालय में 2019 से एक याचिका लंबित है, जिसमें 2012 के रेगुलेशन को चुनौती दी गई है, जिन्हें अब 2026 के रेगुलेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 2012 के रेगुलेशन की जांच करते समय हम इससे अधिक पीछे नहीं जा सकते। सीजेआई ने कहा कि एसजी, कृपया इस मामले की जांच के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति गठित करने के बारे में सोचें ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ विकास कर सके। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अनुच्छेद 15(4) राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है. लेकिन हम आपकी बात समझते हैं, प्रगतिशील कानून में प्रतिगामी रुख क्यों होना चाहिए? न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम अमेरिका जैसे पृथक विद्यालयों में नहीं जाएंगे, जहां अश्वेत और श्वेत अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते थे. मुख्य न्यायाधीश ने कहा बिल्कुल इस तरह की स्थिति का फायदा उठाया जा सकता है. वकील ने राजनीतिक नेताओं के भी बयान हैं, जिनमें कहा गया है कि सामान्य वर्ग के छात्रों को शुल्क देना होगा, इत्यादि। एक वकील ने कहा कि अगर मैं सामान्य वर्ग से हूं और किसी कॉलेज में नया जाता हूं, वहां सीनियर रैगिंग करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई उपचार नहीं है. सीजेआई ने आश्चर्य जताया कि क्या सामान्य वर्ग कवर नहीं है? वकील ने कहा, बिलकुल नहीं ।

सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि हमने नियमों के 3सी की परिभाषा को चुनौती दी है. जाति आधारित भेदभाव किया गया है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भेदभाव समाज में खाई को बढ़ावा देने वाला है। सीजेआई ने कहा कि हम समानता के अधिकार पर गौर कर रहे हैं. यह नियम खरे उतरते हैं या नहीं. आप उस पर दलील दें. जैन ने कहा कि अनुच्छेद 14 में क्लासिफेक्शन को स्पष्ट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इस पर फैसले भी हैं जिनमें स्पष्टीकरण है. जैन ने कहा कि सेक्शन 3सी अनुच्छेद 14 के बिल्कुल विपरीत है. जैन ने कहा कि हम जाति आधारित भेदभाव के इस प्रावधान पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि हमने नियमों के 3ष्ट की परिभाषा को चुनौती दी है. जाति आधारित भेदभाव किया गया है. वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है. शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भेदभाव समाज में खाई को बढ़ावा देने वाला है। सीजेआई ने कहा कि हम समानता के अधिकार पर गौर कर रहे हैं. यह नियम खरे उतरते हैं या नहीं. आप उस पर दलील दें. जैन ने कहा कि अनुच्छेद 14 में क्लासिफेक्शन को स्पष्ट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इस पर फैसले भी हैं जिनमें स्पष्टीकरण है. जैन ने कहा कि सेक्शन 3ष्ट अनुच्छेद 14 के बिल्कुल विपरीत है. जैन ने कहा कि हम जाति आधारित भेदभाव के इस प्रावधान पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।

- यूजीसी के विवादित नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
- नए नियम की भाषा स्पष्ट नहीं है. इसे संशोधित करने की जरूरत है।
- केंद्र प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाए जिसमें शिक्षाविद, न्यायविद और सोशल इंजीनियर्स शामिल हों, वो जांच करेंगे।
- केंद्र को याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विचार करना चाहिए।
- फिलहाल 2012 का यूजीसी नियम लागू रहेगा।

सामान्य वर्ग के लिए बड़ी जीत

ये कहते हुए सीजेआई ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया. अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. अदालत का ये फैसला सामान्य वर्ग के लिए बड़ी जीत है ?योंकि वो सड़कों पर उतरकर नए नियमों का विरोध कर रहे थे लेकिन सवाल जीत-हार का नहीं है बल्कि इस नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ी टिपणियां की, वो बहुत गंभीर हैं.

तो कैंपस के बाहर कैसे आगे बढ़ेंगे?

आप स्कूलों और कॉलेजों को अलग-थलग नहीं रख सकते, अगर कैंपस के अंदर ऐसा माहौल होगा तो लोग कैंपस के बाहर कैसे आगे बढ़ेंगे. संविधान में राज्यों को रूट और रूज के लिए कानून बनाने का अधिकार, लेकिन कानून में भेदभाव नहीं होना चाहिए. यूजीसी के जाति संबंधी नियम अस्पष्ट हैं, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है. इसकी भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत है. ज्यादातर राज्यों में, यहां तक कि विधायिका ने भी महसूस किया है कि अब आरक्षित कमेटी के अंदर भी, लोग अमीर और गरीब बन गए हैं। समुदायों को ग्रुप्स में बांट दिया गया है।

बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, सामाजिक तनाव का वातावरण नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी में भी अपरकास्ट समाज को उचित प्रतिनिधित्व दे देती।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी. बात सिर्फ नियम नहीं, नीयत की भी होती है. न किसी का उत्पीडन हो, न किसी के साथ अन्याय. टीएमसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. बीजेपी ने भी फैसले को सही ठहराया है।

2012 का नियम क्या कहता है?

2012 के नियम की जगह यूजीसी ने 13 जनवरी को नया नियम लागू किया था. कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल पुराना नियम जारी रहेगा तो सवाल है कि 2012 का नियम क्या कहता है? 14 साल पहले UGC ने Higher Educational Institutions में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव को रोकने के लिए नियम बनाए थे. पुराने नियम जाति, धर्म, लिंग और भाषा सहित सभी प्रकार के भेदभाव पर लागू होते थे. कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान SC/ST कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव

अब यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक

बदरी-केदार व गंगोत्री में भी नो एंट्री

एजेंसी

बड़कोट (उत्तरकाशी)। गंगोत्री धाम के बाद अब यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों के प्रवेश को वर्जित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले हरकी पैड़ी और बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

गंगोत्री धाम के बाद अब यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों के प्रवेश को वर्जित करने का निर्णय लिया गया है। यमुनोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि आगामी अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान धाम में नियम लागू कर दिया जाएगा। वहीं प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज सहित अन्य संतों के साथ हुए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की।

उन्होंने कहा सनातन की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों के प्रवेश को वर्जित करने का निर्णय लिया गया है। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान धाम में नियम लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी गैर सनातनी को धाम के आसपास प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस मौके पर बड़कोट व्यापार मंडल महामंत्री सोहन गैरोला भी रहे। बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के अलावा बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अधीन आने वाले 45 से ज्यादा मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। बीकेटीसी की ओर से आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तीर्थ की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्रीगंगा सभा ने हर की पैड़ी समेत कई घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को निषेध कर दिया। इस बारे में विभिन्न जगहों पर बैनर व बोर्ड लगा दिए गए हैं। श्रीगंगा सभा ने ब्रिटिश हुकूमत में लागू म्यूनिसपल एक्ट के तहत यह कदम उठाया है। बोर्ड में स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हरकी पैड़ी समेत मालवीय द्वीप व अन्य घाटों पर लगे इन बैनरों की शुक्रवार को लोगों को चर्चा रही। इसमें श्रीगंगा सभा ने स्पष्ट तौर पर लिख दिया कि घाटों पर किसी तरह से फिल्मी गीत पर वीडियो या रील्स बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

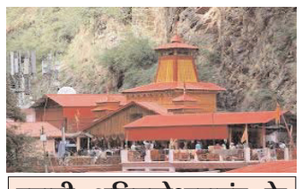

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा

यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि यूपी के प्रयागराज में जिस तरह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोका गया उससे सनातनियों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह सनातन धर्म के खिलाफ है और सनातन धर्म के प्रहरियों की आवाज दबाने की साजिश रची जा रही है।

वोटर लिस्ट से काटे जा रहे नाम, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, फॉर्म 7 के दुरुपयोग का आरोप

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्ट्रक्र के दौरान बड़े पैमाने पर फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. पार्टी का दावा है कि कुछ राज्यों में सुनियोजित तरीके से फर्जी फॉर्म-7 दाखिल कर दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक पहले बड़े पैमाने पर फॉर्म-7 छपवाए गए, फिर हर बूथ पर सामूहिक आपत्तियां दाखिल कराई गई. कई मामलों में आपत्ति की सूचना मतदाताओं तक पहुंची ही नहीं और सीधे अंतिम सूची में नाम गायब कर दिए गए। कांग्रेस का कहना है कि यह पैटर्न राज्य दर राज्य दोहराया जा रहा है, जिसे लेकर ईमानदार बीएलओ और नागरिक भी सवाल उठा रहे हैं।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्ट्रक्र के दौरान बड़े पैमाने पर फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. पार्टी का दावा है कि कुछ राज्यों में सुनियोजित तरीके से फर्जी फॉर्म-7 दाखिल कर दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक पहले बड़े पैमाने पर फॉर्म-7 छपवाए गए, फिर हर बूथ पर सामूहिक आपत्तियां दाखिल कराई गई. कई मामलों में आपत्ति की सूचना मतदाताओं तक पहुंची ही नहीं और सीधे अंतिम सूची में नाम गायब कर दिए गए. कांग्रेस का कहना है कि यह पैटर्न राज्य दर राज्य दोहराया जा रहा है, जिसे लेकर ईमानदार बीएलओ और नागरिक भी सवाल उठा रहे हैं।

मुश्किल दौर में भारत की रफ्तार तेज :पीएम मोदी

एजेंसी

नई दिल्ली। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई आर्थिक समीक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने इस दस्तावेज को भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस की एक व्यापक तस्वीर बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थिरता और प्रगति दिखाई है, यह सर्वे उसी का प्रमाण है। बजट से ठीक पहले आए इस सर्वे पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बयानों के जरिए आसान भाषा में समझिए कि सरकार इसे किस नजरिए से देख रही है और इसके बड़े मायने क्या हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत की निरंतर प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने जोड़ देकर कहा कि यह आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि समावेशी विकास के महत्व के बारे में बताता है। पीएम ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में किसानों, एमएसएमई, युवाओं के रोजगार और समाज कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2026 भारत को विकसित बनाने की दिशा में हमारी यात्रा को तेज करने का खाका पेश करता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और उत्पादकता बढ़ाने के रोडमैप पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि सर्वे में दिए गए सुझाव भविष्य की नीतियों को सही दिशा देंगे और भारत के आर्थिक भविष्य में भरोसा बढ़ाएंगे।

गुरुवार को जारी आर्थिक सर्वेक्षण में सबसे बड़ी राहत वृद्धि दर के आंकड़ों को लेकर है। सर्वे के मुताबिक, अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष (2026-27) में भारत की अर्थव्यवस्था 6.8त्न से 7.2त्न की दर से बढ़ेगी। चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.4त्न रहने का अनुमान है। इसके साथ ही भारत लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। खास बात यह है कि भारत की %संभावित विकास दर% के अनुमान को 6.5त्न से बढ़ाकर अब 7त्न कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण के बाद भारत की मजबूत स्थिति का श्रेय पीएम मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि भारत के मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा, ÷हमने वैश्विक बाधाओं का सफलतापूर्वक सामना किया है और भारत को उच्च विकास के रास्ते पर ला खड़ा किया है÷। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सर्वे में राष्ट्र निर्माण में इनोवेशन (नवाचार), एंटरप्रेन्योरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

सोना-चांदी बेकाबू, बेटियों की शादी पर संकट : डांगी

एजेंसी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की प्रति सदन के पटल पर रखी. उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान सामान्य ढंग से कामकाज हुआ. उच्च सदन में कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने सोने और चांदी की कीमतों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि देश में सोने और चांदी की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं. ग्रामीण भारत खासकर महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर टूट चुकी है। नीरज डांगी ने कहा कि पिछले 13 महीनों में चांदी की कीमतों में 306त्न और सोने की कीमतों में 111त्न की वृद्धि देखने को मिली है. जिस देश में सोना-चांदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हो, वहां इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की गंभीर विफल आर्थिक नीति को दर्शाता है. आज किसान, श्रमिक, निम्न और मध्यम वर्ग के लोग अपनी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आभूषण तक नहीं खरीद पा रहे हैं।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत

❖ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण-2025-26 पेश किया।

❖ पिछले एक साल में ग्रामीण इलाकों में महंगाई शहरी क्षेत्रों से कम रही।

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। इसके तुरंत बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही अब एक फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रस्तुति के एक घंटे बाद शुरू होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक स्थिति का आधिकारिक आकलन प्रस्तुत किया गया है। इसमें आर्थिक विकास, प्रमुख संकेतकों, उपलब्धियों और अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों का उल्लेख किया गया है, साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक परिदृश्य का भी खाका पेश किया गया है। यह दस्तावेज वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) की निगरानी में अंतिम रूप दिया गया। सर्वेक्षण में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन और नीतिगत संकेतों को समाहित किया गया है।

पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट यानी आर्थिक विकास दर अगले वित्त वर्ष 2027 में 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो तीन साल पहले 6.5 प्रतिशत थी। सर्वे के अनुसार, देश में लगातार हो रहे घरेलू सुधार और सरकारी निवेश की वजह से, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की अंदरूनी ताकत बढ़ी है। देश में पिछले एक साल के दौरान ग्रामीण इलाकों में महंगाई शहरी इलाकों की तुलना में कम रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक दबाव में कमी आई है। पिछले दो वर्षों 2023 और 2024 में ग्रामीण महंगाई शहरी महंगाई से ज्यादा थी, लेकिन 2025 में खाने-पीने की चीजों की कीमतें घटने से इसमें कमी आ गई। सर्वेक्षण में बताया गया है कि ज्यादातर राज्यों में खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 2-6 प्रतिशत के सहनशीलता दायरे (टॉलरेंस बैंड) के अंदर रही। इस दौरान केवल केरल और लक्षद्वीप में खुदरा महंगाई 6 प्रतिशत से ऊपर गई। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में महंगाई राष्ट्रीय औसत से कम रही, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में औसत से ज्यादा दर्ज की गई। सर्वेक्षण में राज्य-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई) महंगाई डेटा का भी विश्लेषण किया गया है। जनवरी 2014 से दिसंबर 2025 तक के मासिक आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि राज्यों में महंगाई का अंतर पूरी तरह अस्थायी नहीं था।

नम आंखों से दी गई दादा को अंतिम विदाई

पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटों ने दी मुखाग्नि

एजेंसी

मुंबई । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख नेता अजित पवार (66) का गुरुवार को बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के अंतिम संस्कार किया गया। बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितीन गडकरी, रामदास आठवले, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित प्रमुख नेताओं ने अजीत पवार को पुष्पचक्र अर्पित कर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्नी सुनेत्रा पवार, बेटा पार्थ पवार, जय पवार और पवार परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अजित पवार को आखिरी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अपने नेता के आखिरी दर्शन करने के लिए समर्थकों की भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने नम आंखों से अजित पवार को अंतिम विदाई दी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार को बारामती में हुए प्लेन क्रैश हादसे में निधन हो गया। यह हादसा लैंडिंग की कोशिश करते वक्त हुआ था। इस हादसे में उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर की भी मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। बुधवार शाम को अजित पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान में लाया गया था। इसके बाद आज सुबह पार्थिव शरीर बारामती स्थित काठेवाड़ी में लाया गया। काठेवाड़ी से अजित पवार की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा बारामती ÷दादा, वापस आ जाओ÷ की आवाज से गुंज उठा। समर्थकों ने 'एक वादा अजीत दादा' के नारे लगाकर उन्हें आखिरी विदाई दी।

अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र और बारामती में गम का माहौल है। पवार परिवार और बारामती के लोगों के बीच का रिश्ता अटूट है। इस परिवार ने अपनी उपलब्धियों से देश और राज्य की राजनीति में अपना नाम बनाया है। वरिष्ठ नेता शरद पवार ने 1988 में बारामती की बागडोर अजित पवार को सौंपी थी। उसके बाद अजित पवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बारामती के लोगों ने उन्हें सात बार विधायक चुनकर उनसे बहुत प्यार किया। बारामती के लोगों के लिए काम करने वाले अजित पवार ने बारामती की धरती पर ही आखिरी सांस ली। बारामती को देश का नंबर वन शहर बनाने का उनका सपना अधूरा रह गया। अभी बारामती में कई प्रोजेक्ट पूरे होने की कगार पर हैं, जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज, करहा नदी का ब्यूटीफिकेशन, करहा-नीरा योजना, जो खेती लायक इलाकों के लिए वरदान साबित होगी और शिवश्रुति।

सम्पादकीय

पवार हादसा और वीवीआईपी हवाई सुरक्षा पर उठते सवाल

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु केवल एक व्यक्ति की असमय विदाई नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था पर कठोर प्रश्नचिह्न है, जो वीवीआईपी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताती है पर व्यवहार में बार-बार असफल होती दिखाई देती है। बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ यह हादसा, जिसमें पवार सहित पांच लोगों की जान चली गई। देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि तकनीक, नियम और निगरानी के बीच कहीं गंभीर चूक है, जो वीवीआईपी समेत आमजन पर भी भारी पड़ती है। प्रारंभिक तथ्यों के अनुसार, विमान ने लैंडिंग की पहली कोशिश असफल होने पर दोबारा उतरने का प्रयास किया। दूसरी कोशिश में विमान रनवे से पहले ही गिर पड़ा और आग लग गई। न आपात संकेत भेजा गया, न 'मेडे' कॉल। तकनीकी खराबी और लैंडिंग गियर की समस्या की आशंका जताई जा रही है। फिर भी, यह प्रश्न अभी से उठ खड़ा हुआ है कि क्या वीवीआईपी उड़ानों में जोखिम-प्रबंधन उतना सुदृढ़ है, जितना दावा किया जाता है। यह हादसा किसी एक क्षण की गलती का परिणाम हो सकता है पर इसके पीछे की पृष्ठभूमि लंबी है। छोटे हवाई अड्डों की सीमित संरचना, निजी चार्टर सेवाओं की निगरानी, मौसम और नेविगेशन सूचना की गुणवत्ता और सबसे अहम, निर्णय लेने की प्रक्रिया में दबावों की भूमिका। जब उड़ानें समय-सारिणी और राजनीतिक कार्यक्रमों से बंध जाती हैं तो क्या सुरक्षा के निर्णयों पर अनकहा दबाव बनता है? यह पहली बार नहीं है, जब भारत ने विमान हादसों में अपने नेतृत्व को खोया है। अजित पवार की दुर्घटना हमें उन पुराने जख्मों की याद दिलाती है, जो समय के साथ भी भरे नहीं हैं। संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, जी.एम.सी. बालयोगी, वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, सीडीएस बिपिन रावत, होमी जहांगीर भाभा, विजय रूपाणी और ओपी जिंदल व चौधरी सुरेंद्र सिंह जैसे नाम केवल व्यक्ति नहीं, संस्थागत क्षति के प्रतीक थे। हर बार शोक व्यक्त हुआ, जांच बैठी, रिपोर्टें आईं पर क्या व्यवस्थागत सुधार स्थायी रूप से लागू हुए? यदि होते, तो ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों दोहरातीं? यह केवल तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति, जवाबदेही और पारदर्शिता का प्रश्न है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का जीवन निजी नहीं होता। उनका अस्तित्व शासन की निरंतरता, नीति-निर्माण और सार्वजनिक हित से जुड़ा होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा को भावनात्मक सहानुभूति के बजाय संस्थागत जिम्मेदारी के रूप में देखना होगा। वीवीआईपी उड़ानों के लिए स्वतंत्र और नियमित सुरक्षा ऑडिट, पायलट के निर्णय की पूर्ण स्वायत्तता, आधुनिक नेविगेशन और लैंडिंग सहायता प्रणालियों की अनिवार्यता ये अब विकल्प नहीं, आवश्यक शर्तें हैं। विशेषकर छोटे हवाई अड्डों पर संरचनात्मक मानकों की समीक्षा जरूरी है। रनवे की दृश्यता, ग्राउंड-सपोर्ट सिस्टम, मौसम-डेटा की रियल-टाइम उपलब्धता और आपात प्रतिक्रिया की तैयारी इन सब पर समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। निजी चार्टर कंपनियों पर भी वही सख्त नियम लागू होने चाहिए जो वाणिज्यिक उड़ानों पर होते हैं और उल्लंघन पर दंड केवल कागजी न रहकर वास्तविक और प्रभावी होना चाहिए। नागर विमानन मंत्रालय को एक व्यापक 'नेशनल वीवीआईपी एयर सेफ्टी पॉलिसी' लागू करनी चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इस त्रासदी से व्यवस्था बदलें, ताकि भविष्य में कोई उड़ान, कोई जीवन और कोई जिम्मेदारी इस तरह अधर में न रहे।

नमन
नृपेन्द्र अभिषेक नृप

राजनीति के अनुभवी स्तंभ थे अजित पवार

अजित पवार, जो दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत स्तम्भ रहे हैं, विमान लैंडिंग हादसे का शिकार हो गए। उनकी पहचान केवल एक राजनेता के तौर पर नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसे नेता थे जिन्हें जनता ने 'दादा' कहकर सम्मान दिया। इस संबोधन में एक भावनात्मक जुड़ाव झलकता था– एक ऐसा सम्मान जो वे वर्षों के जन-समर्थन, बातचीत और कार्यों के कारण अर्जित कर पाए थे। उनकी कार्यशैली तेज़, निर्णायक और प्रभावशाली रही। वे हमेशा जनता के बीच संवाद बनाए रखने में विश्वास रखते थे। पवार का अचानक और अप्रत्याशित निधन न केवल एक नेता की मृत्यु है, बल्कि महाराष्ट्र राजनीति के एक अद्वितीय अध्याय का अंत भी है।

बुधवार की सुबह, जब महाराष्ट्र की राजनीति नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने वाली थी, एक ऐसी खबर ने सबको हैरान कर दिया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अजित पवार, जो दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत स्तम्भ रहे हैं, अपने निजी विमान से बारामती की ओर जा रहे थे, तब उनका विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पवार सहित सभी सवारों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक अधिकारियों के अनुसार लैंडिंग की प्रक्रिया के दौरान विमान संतुलन खो बैठा और रनवे के पास ही जोरदार टक्कर के साथ क्रैश-लैंड हो गया, जिससे यह भयावह दृश्य बना।

यह दुर्घटना राज्य के लिए एक बड़ा सदमा है, जिसने राजनीतिक, प्रशासनिक और जनता के सामूहिक मन को झकझोर दिया है। अजित अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देओलाली-प्रवरा में हुआ था। वह एक राजनीतिक परिवार से थे, जिनके चाचा शरद पवार भारतीय राजनीति के अग्रणी नेतृत्व रहे हैं। युवा अवस्था से ही उन्होंने राजनीति में रुचि विकसित की और समाज सेवा तथा संगठनवाद में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका राजनीतिक सफ़र सहकारी आंदोलन से शुरू हुआ। 1982 से उन्होंने स्थानीय और ग्रामीण राजनीतिक कार्यों में भाग लिया और जल्दी ही अपने तेज़ संगठनात्मक कौशल के कारण लोकप्रिय हो गए। 1991 में उन्होंने बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिसके बाद वे महाराष्ट्र राजनीति के केंद्र में आ गए। उनकी राजनीतिक यात्रा केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में 16 वर्ष तक काम किया, जहां से उन्हें ग्रामीण और सहकारी क्षेत्रों में व्यापक समर्थन मिला। इससे उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे मजबूत नेताओं में से एक बनाया गया। वह बारामती निर्वाचन क्षेत्र से कई बार लगातार विधायक चुने गए और विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों जैसे कृषि, बागवानी, बिजली, जल संसाधन और वित्त एवं योजना मंत्रालयों का नेतृत्व किया। विशेष रूप से जल संसाधन विभाग में उन्होंने कृष्णा घाटी तथा कोकण सिंचाई जैसी परियोजनाओं पर काम किया, जिससे कृषि-आधारित समुदायों को व्यापक लाभ हुआ। अजित पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनूठा योगदान दिया। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत से राज्य के शासन में कई महत्वपूर्ण पद संभाले और विविध सरकारों में अपना स्थान बनाए रखा। 2010 में उन्हें पहली बार उपमुख्यमंत्री का पद प्राप्त हुआ, लेकिन 2013 में सिंचाई घोटाले के आरोपों के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में क्लीन चिट मिलने के बाद वे फिर से पद पर लौट आए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक चुनौतियों ने भी उनके सामर्थ्य को कम नहीं किया। आज वह महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले उपमुख्यमंत्रियों में से एक माने जाते थे, और उनके प्रशासनिक कौशल तथा संगठन शक्ति की वजह से उन्हें विशेष सम्मान मिला। उनके योगदान ने कई योजनाओं और नीतियों को आकार दिया, जिससे राज्य के विकास की दिशा प्रभावित हुई।

राजनीति में किसी भी नेता का सफ़र विवादों से मुक्त नहीं रहता और पवार भी इससे अछूते नहीं थे।

2013 में दिया गया एक विवादित बयान जब आलोचना की भेंट चढ़ा, तब उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को धमकाने के आरोप भी लगे। समय-समय पर भ्रष्टाचार तथा पद दुरुपयोग के मुद्दों ने भी उनके राजनीतिक जीवन को जटिल बना दिया। लवासा लेक सिटी जैसी परियोजनाओं में कथित मदद के आरोपों ने भी उनके व्यवहार को लेकर सुर्खियां बनाई। इन विवादों के बावजूद उनका जन-समर्थन और राजनीतिक प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि उनके प्रशंसकों का मानना रहा कि प्रशासनिक क्षमता तथा संगठनात्मक कौशल ने उनके विवादों को परास्त किया। उनकी राजनीतिक छवि अक्सर विरोधाभासी रही, जहां एक ओर आलोचक उन्हें कठोर राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल मानते थे, वहीं समर्थक उन्हें एक कुशल, अनुभवी और लोक-सम्मानित नेता के रूप में देखते थे। इसी विरोधाभासी छवि ने उन्हें महाराष्ट्र राजनीति का एक मजबूत स्तम्भ बनाया। अजित पवार की पहचान केवल एक राजनेता के तौर पर नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसे नेता थे जिन्हें जनता ने "दादा" कहकर सम्मान दिया। इस संबोधन में एक भावनात्मक जुड़ाव झलकता था- एक ऐसा सम्मान जो वे वर्षों के जन-समर्थन, बातचीत और कार्यों के कारण अर्जित कर पाए थे। उनकी कार्यशैली तेज़, निर्णायक और प्रभावशाली रही। वे हमेशा जनता के बीच संवाद बनाए रखने में विश्वास रखते थे। बारामती और उसके आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने जल कृषि, आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश के माध्यम से उन समुदायों को सीधे रूप से लाभ पहुंचाया। उनके नेतृत्व में कई योजनाएं और बजट पर निर्णय महाराष्ट्र की आर्थिक दिशा में स्थिरता और विकास का आधार बने। उनका नाम कई बार राज्य के बजट तैयार करने वाले नेता के रूप में भी सामने आया, क्योंकि उन्होंने वित्तीय मामलों में गहरी समझ और विस्तृत बारीकी दिखाई। अजित पवार महाराष्ट्र के उन नेताओं में थे जिन्होंने राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब-जब भी गठबंधन सरकारों के बीच सत्ता के समीकरण बदलते, पवार अपनी समझदार रणनीतियों के कारण राजनीतिक निर्णयों पर असर डालते रहे। उनकी राजनीतिक सूझ-बूझ ने अक्सर नीतिगत दिशा को प्रभावित किया, और कई बार गठबंधन निर्णय उनके प्रभाव के बिना सम्भव नहीं थे। यह अकेला कोई कार्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक कला थी, जिसमें उन्होंने संगठन शक्ति, कौशल और प्रशासनिक अनुभव को शासकीय निर्णयों के साथ जोड़कर एक संगठित राजनीति की मिसाल पेश की। कई विश्लेषक मानते हैं कि उनके अनुभव की वजह से शासन-प्रशासन में संतुलन बन रहा था और निर्णय लेने में उनकी भूमिका निर्णायक थी। आज पवार के अचानक निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक विशाल खालीपन महसूस किया जा रहा है। एक ऐसा नेता जिसने न केवल राजनीतिक मशीनरी को समझा, बल्कि उसे दिशाहीन समयों में भी मजबूती से थामा, अब नहीं रहे। उनकी मौत से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति केवल पदों और शक्ति का नाम नहीं है; यह एक जन-सम्बंध, प्रशासन क्षमता, दूरदर्शिता और संघर्ष का मिश्रण है। पवार ने इन सभी चरित्रों को अपने जीवन में बख़ूबी अपनाया और महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में अपनी एक स्थायी पहचान बनाई। आज वे नहीं हैं, पर उनकी याद, चर्चा और उनके कार्यों का प्रभाव लंबे समय तक राजनीति के परिदृश्य पर देखा जाएगा। अजित पवार का अचानक और अप्रत्याशित निधन न केवल एक नेता की मृत्यु है, बल्कि महाराष्ट्र राजनीति के एक अद्वितीय अध्याय का अंत भी है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

आर्थिकी

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

विकास केंद्रित रणनीतिक बजट की उम्मीद

इन दिनों पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले बजट की ओर लगी हुई है। सीतारमण का यह नौवां बजट होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में जहां भारत के यूरोपीय संघ (ईयू) सहित विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कारोबार और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में साहसिक सुधारों की गति बढ़ाने की रणनीति होगी, वहीं 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के दृष्टिकोण से खपत और व्यय बढ़ाकर विकास दर बढ़ाने की भी विशेष रणनीति होगी। साथ ही गरीब, युवा, महिलाएं, किसान और मध्यम वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ रक्षा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), हरित ऊर्जा और आर्थिक सुधारों पर बड़े ऐलान दिखाए देंगे। वित्त मंत्री राहत और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 फीसदी के स्तर पर सीमित रखने और 7.5 फीसदी विकास दर पाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगी। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण के समक्ष वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करते समय चुनौतियों की शृंखला सामने है। वर्ष 2026-27 में राज्यों के साथ संसाधनों के बंटवारे को लेकर सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने पर भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होगा। इन चुनौतियों के बावजूद इस समय वित्त मंत्री की मुठ्ठियों में विभिन्न वर्गों को राहत देने और विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रभावी आवंटन हेतु कर संग्रहण संबंधी मजबूत परिदृश्य मौजूद हैं। चालू वित्त वर्ष के तहत 7.4 फीसदी विकास दर प्राप्ति के संकेत अच्छे आर्थिक परिदृश्य के प्रतीक हैं। चालू वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में प्रभावी वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर 2024 तक आयकर सहित प्रत्यक्ष कर संग्रहण 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 8 फीसदी से भी ज्यादा है। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री आगामी वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12 से 12.5 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचाते हुए दिखाई देंगी। नए बजट में महिलाओं के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड, ऋण तथा बीमा प्लान की घोषणाएं हो सकती हैं।

नए बजट में वित्त मंत्री रोजगार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा वेयरहाउसिंग संबंधी प्रोत्साहन, पीएलआई योजना का दायरा बढ़ाने, रियल एस्टेट सेक्टर और आवास सेक्टर को प्रोत्साहन, डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना तथा स्वच्छ ऊर्जा के लिए अधिक आवंटन करते हुए दिखाई दे सकती हैं। प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना की शुरुआत संभावित है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण पर अधिक आवंटन संभावित है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रेलवे, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और क्षमता संवर्धन के साथ दीर्घावधि वृद्धि को बनाए रखने, वैश्विक क्षमता निर्माण और एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड के नए सुधार नए बजट के माध्यम से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेंगे। साथ ही आगामी बजट के माध्यम से वित्त मंत्री सीतारमण तेज विकास के लिए जरूरी और वित्तीय सुधारों को लागू करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग जगत की लाजिस्टिक्स लागत घटाने, रोजगार सृजित करने वाले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने संबंधी बुनियादी रणनीतियां प्रस्तुत करते हुए दिखाई देंगी। यह भी संभावना है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री युवाओं के बीच रोजगार बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन को बेहतर करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों से सजाते हुए दिखाई दे सकती हैं। वित्त मंत्री सीतारमण नए बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उधार की सीमा बढ़ाने और खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए आपूर्ति संबंधी नए कदमों के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। वित्त मंत्री तेज रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाकर नए रोजगार अवसरों को निर्मित कर सकती हैं। उम्मीद करें कि नया बजट आम आदमी के लिए राहत, बाजार के लिए रफ्तार और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट होगा।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

गलत सोच का चश्मा जल्दी उतार देना चाहिए

संकलित
दर्शन

जब सोच निषेधात्मक या गलत होती है, तब वह सुख को भी दुख में परिवर्तित कर देती है। गलत सोच का चश्मा जितनी जल्दी हो, उतार देना चाहिए। बुरे विचार जितना दूसरों का नुकसान करते हैं, उतना ही स्वयं का भी करते हैं। कारण अपनी ही सुरक्षा को लेकर डरा दिमाग ढंग से नहीं सोच पाता। हम स्वार्थी हो जाते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। कहा गया है कि आपके विचार वहां तक ले जाते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं। पर कमजोर विचारों में दूर तक ले जाने की ताकत नहीं होती। हम जो हैं वह सब विचारों का फल है। जो हम सोचते हैं, वही बन जाते हैं। मनुष्य अपने कार्यों से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और अपने विचारों से स्वयं को। गलत सोच एवं अनैतिक कार्यों में लिप्त लोगों को धनवान और प्रतिष्ठित होते देख आदमी में नकारात्मक चिंतन जागता है। अपनी ईमानदारी उसे मूर्खतापूर्ण लगती है। वह पुनर्चिंतन करता है-क्या मिला मुझे आदर्शों पर चलकर? यह नकारात्मक चिंतन उसे भी गलत सोच के दलदल में उतार देता है। समाज में भ्रष्ट और बेईमान लोगों की उत्पत्ति इसी तरह के गलत विचारों के संक्रमण से हुई। इस तरह का गलत सोच हमारी दुनिया को छोटा कर देता है। भीतर और बाहरी दोनों ही दुनिया सिमट जाती हैं। तब हमारी छोटी-सी सफलता अहंकार बढ़ाने लगती है। थोड़ा-सा दुख अवसाद का कारण बन जाता है। कुल मिलाकर सोच ही गड़बड़ हो जाता है। अपने ही बोले हुए को सुनते रहना ज्यादा सीखने नहीं देता।

तुलसीदास ने बताया श्रीराम के दर्शन का उपाय

संकलित
प्रेरणा

एक ब्राह्मण दिनभर गोस्वामी जी के कुटिया के बाहर बैठकर लोभवश राम-राम रटता। संध्या के समय श्रीहनुमान जी उसे धन दे देते थे। एक बार उसने भगवान के दर्शन के लिए बड़ा हठ किया। गोस्वामी जी ने कहा- उसके लिए प्रेम और भाव चाहिए, संत की कृपा चाहिए। ऐसे ही एकदम भगवान नहीं मिलते। उसने कहाः आप समर्थ महापुरुष है, आप भगवान के दर्शन करवा सकते है। वह हठ पर अड़ गया। गोस्वामी जी ने कहाः ठीक है यहाँ सामने इस पेड़ पर चढ़ जाओ, पेड़ के नीचे त्रिशूल गाढ़ दो और उस त्रिशूल पर कूद पडो। भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वह त्रिशूल गाडकर वृक्षपर चढ़ा, परंतु कूदने की हिम्मत नहीं हुई। एक घुडसवार उधर से जा रहा था, उसने पूछाः पेड़ पर क्या कर रहे हो? ब्राह्मण बोलाः तुलसीदास जी ने कहा है पेड़ पर से त्रिशूल पर कूदो तुम्हे भगवान श्रीराम के दर्शन होंगे। उस व्यक्ति ने कहा- क्या सच में यह बात तुलसीदास जी के श्रीमुख से निकली है? ब्राह्मण बोला- जी हां ! वह व्यक्ति तुरंत पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ा। उसे भगवान ने आकर हाथ से पकड़ लिया और उसे श्रीराम के दर्शन प्राप्त हो गए। हनुमान जी ने उसे तत्त्वज्ञान का उपदेश भी दिया। गोस्वामी जी ने सत्य ही कहा था, जिनमें प्रेम-भाव हो एवं संत की कृपा हो वही भगवान के दर्शन पाता है।

सटाका

आज की पाती

लाला लाजपतराय का प्रेरणादायक जीवन

भारत में बहुत से महापुरुष हुए। इन महापुरुषों ने भारत को ही नहीं, बल्कि दुनिया को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए बहुत से काम किए और दुनिया के लिए प्रेरक बनें। इन्हीं में से एक थे लाला लाजपतराय। उनका जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब में हुआ था। वह लेखक, वकील, क्रांतिकारी और बहुत से अच्छे गुणों से परिपूर्ण थे। उनका देश की आजादी में भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध वर्ष 1928 में किया था। इस विरोध के कारण उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। उन्हें पंजाब का शेर और पंजाब केसरी की उपाधि से नवाजा गया था। उन्होंने आर्य समाज के लिए भी काम किया था। उनकी जयंती पर राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। – *प्रतीक जैन, धमतरी*

ट्रेंड

महिला नेतृत्व विकास

मोदी सरकार का स्पष्ट मानना है कि देश का समग्र विकास तभी संभव है, जब सभी देशवासियों को समान अधिकार और अवसर मिलें। इसी सोच के तहत आज भारत महिला नेतृत्व विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
-अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला विकास मंत्री

दिलदार मित्र खोया

ज़मीन से जुड़े जननेता और सहयोगी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार की विमान दुर्घटना में निधन की खबर से मन व्यथित है। मैंने अपना एक दमदार और दिलदार मित्र खो दिया है। यह घटना महाराष्ट्र के लिए अत्यंत पीड़ादायक है।
- देवेंद्र फडणवीस, सीएम, महाराष्ट्र

झुग्गी बस्तियों का विकास

हमारी सरकार ने झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए अलग से 700 करोड़ का विशेष फंड निर्धारित किया है। यह केवल बजट प्रावधान नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का ठोस संकल्प है कि मूलभूत सुविधाएं और गरिमा भरा जीवन हर परिवार तक पहुंचे।
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

सनातनी परंपरा

भाजपा के दंभ ने अनादिकाल से चली आ रही सनातनी परंपरा को तोड़ दिया है। जगद्गुरु शंकराचार्य का तीर्थराज प्रयाग की धरती पर माघमेले को बिना पवित्र स्नान किए छोड़कर जाना एक अत्यंत अनिष्टकारी घटना है।
-अखिलेश यादव, सांसद, सपा

पर्यटन के बूट

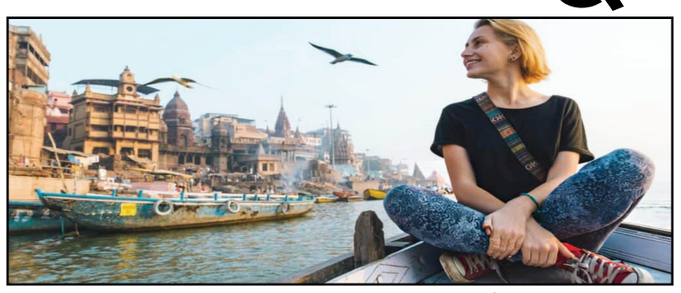

पर्यटन के रास्ते आ रहा फूहड़पन और हिमाचल की तस्वीर में बहती गंदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अक्सर सोशल मीडिया के खंडहर स्थापित हो जाते हैं। हिमाचल में ऐसा बहुत कुछ है जो आह्लादित और रोमांचित करता है। यहां हर मौसम दिल तक के रंग बदलता है। मसलन बर्फ के सान्निध्य में पर्यटन का उफान आजकल जिस कद्र छाया है, उसके साथ खुली छूट नहीं दी जा सकती। बर्फ का कचूमर निकालना पर्यटन नहीं और न ही वाहनों से खेलना पहाड़ की सोहबत है। वे दृश्य भयानक हैं जब रिज पर गिरी बर्फ से नहाते पर्यटक अगर अपनी आस्तीन खोल दें या निर्वस्त्र होकर कोई महिला मनाली की फिड्डा बिगाड़ दे। इस शोरगुल में बर्फ भी बहरी हो गई, प्रकृति गाती रही हम भी सुन न सके। प्रकृति की छूअन का हल्का सा आमंत्रण आंखों में बहारों सा शगुन है, लेकिन पर्यटन के अति दोहन ने हमसे हमारी मौलिकता छीन ली है। हिमाचल को मौसमी पर्यटन की महफिल जरूर मिलती है, लेकिन यह चार दिन की चांदनी बनकर प्रदेश के ओज को बौना कर देती है। ऐसे पर्यटन के आगे जो देखा जा सकता है, उसे कैसे बचाएं-दिखाएं। यह नागरिक जवाबदेही भी है कि पर्यटन को प्रकृति की रचना में संजोएं। तारीफ करनी होगी लाहौल-स्पीति के सिस्सू-कोकसर इलाके के लोगों की, जिन्होंने अपने हलडा उत्सव की मयार्दा को कायम रखते हुए 40 दिनों तक पर्यटन गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह इसलिए भी कि अटल टनल ने पर्यटन को दरिया बना दिया है और अगर सिस्सू के नागरिक, आमंत्रण और परंपरा के बीच पहाड़ के मर्म की रक्षा न करते तो सैलानियों के बूट किसी भी स्तर तक पहुंच कर कुछ भी रौंद देते। यही सब इस बर्फबारी के मंजर में तबाह भी हुआ है। आखिर बर्फ केवल पर्यटन के लिए ही तो नहीं आती। वह पहाड़ को पहाड़ की दरियादिली में दिखाने के लिए आती है। वह कृषि, फलोत्पादन व नदियों के प्रवाह में आत्मविश्वास लेकर आती है। इसलिए बर्फ के हर गिरे हुए फाहे पर पर्यटन का हक नहीं हो सकता। इसी तरह प्राकृतिक हलचल या प्राकृतिक छटा के हर मजमून से सोशल मीडिया को आबाद करना भी गुनाह है। कोई महिला बाहर से आकर मनाली के सार्वजनिक शिष्टाचार भूल कर नग्नावस्था में अश्लील डांस करे, तो इससे भयानक पर्यटन आकर्षित होगा।

अभी भी अंतरराष्ट्रीय हलकों में मलाणा क्रीम का जिक्र मात्र हिमाचल को नशे की मंडी बना देता है। धीरे-धीरे हिमाचल के ही कुछ इलाके गोपनीय पार्टियों के इश्तिहार में बदनाम हो चुके हैं। आखिर 70 लाख की आबादी वाले पहाड़ी, परंपरावादी, कबायली व खास मूल्यों से प्रेरित हिमाचल को कितना और किस तरह के पर्यटन की जरूरत है। हमें पर्यटक परिवार चाहिए, कारपोरेट जगत की युवा पीढ़ी चाहिए, हुल्लड़बाज युवा चाहिए या रील बनाने की उद्दंडता से सराबोर सैलानी चाहिएं। हमारी पर्यटन की मुहिम न पर्यटन सीजन और न ही बर्फबारी या शीतकालीन सफर तक मुकम्मल होती है। जो डलहौजी की बर्फ को रौंद रहे हैं, उन्हें कौन बताएगा चंबा के हजार साल की धरोहर। शिमला में बर्फबारी से इतर ब्रिटिश पीरियड की यादों के झरोखे कौन खोलेगा। कौन कांगड़ा के पर्यटक सीजन को मसरूर, कांगड़ा फोर्ट या सुजानपुर के ऐतिहासिक मैदान तक ले जाएगा। वर्तमान सरकार अगर कांगड़ा को पर्यटन की कैपिटल बना रही है, तो सर्वप्रथम पर्यटकों की राजधानी बनाने के लिए हमें राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, ओडीसा, गुजरात व पश्चिमी बंगाल राज्यों की तर्ज पर ऐसे कई सर्किट बनाने होंगे, जो साल के हर दिन को पर्यटकों के आकर्षण के शिष्टाचार से जोड़ सकें।

शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के कैशलैस इलाज पर 359 करोड़ खर्च करेगी सरकार

संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक सहित अन्य कर्मी और उनके आश्रित सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते वर्ष शिक्षक दिवस-2025 के अवसर पर इस योजना की घोषणा की थी, जिस पर अब मंत्रिपरिषद ने औपचारिक मुहर लगा दी है। इस निर्णय से बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले करीब 11.95 लाख से अधिक शिक्षक, शिक्षा कर्मी और उनके आश्रित परिवार लाभान्वित होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, मानदेय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मी भी इस सुविधा को प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्णय से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत करीब 2.97 लाख से अधिक शिक्षक, शिक्षा कर्मी एवं उनके आश्रित परिवार लाभान्वित होंगे। इस पर लगभग 89.25 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित किया जाएगा। यह सुविधा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की तर्ज पर लागू की जाएगी, जिसमें आईपीडी (अंतरोगी) उपचार पूरी तरह कैशलेस होगा। योजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं परिषद से मान्यता प्राप्त अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन, पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षक, प्रधानमंत्री पोषण योजना से जुड़ी रसोइयां तथा इन सभी के आश्रित परिवार के सदस्य शामिल होंगे। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक (व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित) संस्कृत शिक्षा परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक (मानदेय सहित), माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षक, राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ को आईपीडी (अंतः रोगी विभाग) में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस योजना पर सरकार की ओर से प्रति कर्मी लगभग 3000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के हिसाब से कुल 358.61 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक व्यय किया जाएगा। यह योजना शिक्षा कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फैसले के तहत इस सुविधा का लाभ उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी उठा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि यह योजना आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की तर्ज पर लागू की जाएगी। कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ साचीज से संबद्ध निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होंगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति पहले से केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत आच्छादित हैं, उन्हें इस योजना का अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद से संबद्ध स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को कैशलेस इलाज योजना का लाभ देने से पहले वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा।

परिवहन विभाग के तीन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

संवाददाता

लखनऊ। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के तीन प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 351 सहायक मोटरयान निरीक्षक के पद सृजित किये गये हैं। उप्र परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (यथा संशोधित) नियमावली, 1980 में मोटरयान निरीक्षक के लिए उपबन्ध किये गये हैं। उक्त नियमावली में ही अपेक्षित संशोधन करते हुए सहायक मोटरयान निरीक्षक के नवसृजित 351 पदों के लिए उपबंध किये जाने के संबंध में उ0प्र0 परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। उप्र परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन के उपरांत प्रदेश में 351 सहायक मोटरयान निरीक्षकों की भर्ती/चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।

उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति तेज करने को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। भरोसेमंद, सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति, निवेश और रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाती है। इसी सोच के अंतर्गत प्रदेश में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार लागू किए गए हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है। औद्योगिक विकास के लिए 24 घंटे अबाधित बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करना प्रमुख लक्ष्य है। बीते वर्षों में नए पावर प्लांट की स्थापना, ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार और सब स्टेशनों के निर्माण से बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों और एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर के आसपास बिजली अवसंरचना को विशेष रूप से मजबूत किया गया है, ताकि उद्योगों को निर्बाध आपूर्ति मिल सके और उत्पादन प्रभावित न हो। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए वर्ष 2017 से नवंबर, 2025 के मध्य तक 15,87,369 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित किये जा चुके हैं। 33/11 केवी क्षमता वाले 765 नए सब स्टेशन बनाये गए। 2,455 पुराने विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गई है। कम लागत की बिजली को प्रदेश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने का अहम साधन माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि सस्ती बिजली मिलने से उद्योगों की उत्पादन लागत घटेगी, जिससे वे घरेलू और वैश्विक बाजार में बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीतियों में ऊर्जा लागत को नियंत्रण में रखने पर जोर दिया गया है।

यूपी में घर बनाना हुआ महंगा, पत्थरों से लेकर मौरंग तक की दरों में होगी बढ़ोतरी

संवाददाता

लखनऊ। घर बनाने के लिए अब लोगों को पहले से ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ेगी। प्रदेश में ग्रेनाइट आदि पत्थरों से लेकर मौरंग तक की दरों में बढ़ोतरी होने जा रही है। खनन विभाग ने उपखनिजों के स्वामित्व की दरों और वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेड रेंट) में बढ़ोतरी के लिए उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली-2021 में द्वितीय संशोधन का का प्रस्ताव दिया था, जिसे गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव के तहत ग्रेनाइट साइज्ड डायमेंशनल स्टोन के स्वामित्व की दर को एक मीटर या उससे अधिक आकार के लिए पांच हजार रुपये प्रति घनमीटर से बढ़ाकर छह हजार रुपये प्रति घनमीटर, एक मीटर से कम साइज के लिए तीन हजार रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रति घनमीटर, स्लैब के लिए 650 रुपये प्रति घनमीटर से बढ़ाकर 850 रुपये प्रति घनमीटर की गई है। ग्रेनाइट और डेलोस्टोन के लिए स्वामित्व की दर 160 रुपये प्रति घनमीटर से बढ़ाकर 165 रुपये प्रति घनमीटर, सैंडस्टोन व क्वार्टजाइट के लिए 110 रुपये प्रति घनमीटर से बढ़ाकर 140 रुपये प्रति घनमीटर, नदी तल में उपलब्ध मौरंग के लिए 150 रुपये प्रति घनमीटर से बढ़ाकर 190 रुपये प्रति घनमीटर, पहाड़ों के क्षरण से बनने वाली लाल मौरंग के लिए 75 रुपये प्रति घनमीटर से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति घनमीटर कर दिया गया है। वहीं साधारण बालू की दर में भी 15 रुपये प्रति घनमीटर की वृद्धि की गई है। चूना पत्थर पर पूर्व में स्वामित्व की दर 150 रुपये प्रति टन थी, अब इसे सूची से बाहर कर दिया गया है। इनके अलावा पायरोफिलाइट के लिए स्वामित्व की दर 300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति टन, डायस्पोर के लिए 50 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 525 रुपये प्रति टन, सिलिका सैंड के लिए 100 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति टन कर दी गई है। इसके साथ ही उपखनिजों के लिए वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेड रेंट) भी बढ़ा दिया गया है। सैंड स्टोन एवं क्वार्टजाइट के लिए 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 97,500 रुपये, ग्रेनाइट व डेलोस्टोन के लिए 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये, इमारती पत्थर-गिट्टी के लिए 90 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.35 लाख रुपये, नदी तल की मौरंग के लिए 90 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.35 लाख रुपये, पहाड़ों के क्षरण से मिलने वाली लाल मौरंग के लिए 24 हजार रुपये से बढ़ाकर 36 हजार रुपये, साधारण बालू (प्रथम श्रेणी) के लिए 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये, साधारण बालू (द्वितीय श्रेणी) के लिए 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये, साधारण मृदा के लिए 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं पायरोफिलाइट, डायस्पोर, सिलिका सैंड, चाइना क्ले, कैलसाइट व अन्य उपखनिजों के लिए डेडरेंट 20 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है। हालांकि चूना पत्थर (लाइम स्टोन) के लिए पूर्व में 40 हजार रुपये डेड रेंट था, अब इसे सूची से बाहर कर दिया गया है।

सफल तिरंगा यात्रा के बाद सूरज प्रधान ने पत्रकारों का किया सम्मान

संवाददाता

गोसाईगंज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गोसाईगंज क्षेत्र में आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा की धूमधाम पूर्ण सफलता के उपरांत बुधवार को समाजसेवी सूरज प्रधान ने मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय पत्रकारों का स्वागत-सम्मान समारोह आयोजित किया। यह तिरंगा यात्रा 25 जनवरी 2026 को जे.एन.डी. खेल मैदान (हसनपुर खेवली) से शुरू होकर सुल्तानपुर रोड, एचसीएल तिराहा होते हुए पटेल पार्क, गोसाईगंज पर समाप्त हुई थी। यात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय निवासी, युवा, महिलाएं एवं गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तिरंगा लहराकर राष्ट्रप्रेम एवं एकता का संदेश दिया। यात्रा में प्रमुख रूप से राम सिंह प्रधान, पूर्ण कअर संजीव कुमार, मेजर आर.एल. वर्मा, पार्षद केशव प्रसाद, सुनील कुमार सहित क्षेत्र के कई जाने-माने लोग उपस्थित रहे। आयोजक सूरज प्रधान ने बताया कि पिछले दो महीनों से चल रही तैयारियों के फलस्वरूप यह कार्यक्रम ऐतिहासिक स्तर पर सफल रहा। सफलता के बाद हसनपुर खेवली खेल मैदान पर आयोजित सम्मान समारोह में सूरज प्रधान ने सभी पत्रकारों का व्यक्तिगत स्वागत किया तथा उन्हें नववर्ष डायरी और पेन देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में यात्रा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया। अतिथियों एवं उपस्थितजनों के लिए सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था की गई थी। समारोह में पवन वर्मा, संकेत रावत, विकास रावत, सौरभ रावत, गुड्डू रावत, सचिन, अमित रावत, गोलू, लक्की चौधरी, दिलीप, विवेक, आकाश रावत, अनुज कुमार ने महत्व पूर्ण भूमिका निभाई। सूरज प्रधान ने मीडिया की सराहना करते हुए कहा कि पत्रकारों की सक्रिय भागीदारी एवं कवरेज के बिना इस भव्य आयोजन की सफलता अधूरी रहती। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया और भविष्य में ऐसे देशभक्ति कार्यक्रमों को जारी रखने का संकल्प लिया।

डायरिया से डर नहीं कार्यक्रम के तहत सेवा प्रदाताओं का अभिमुखीकरण

पीएसआई इंडिया व केनव्यू के सहयोग से कार्यशाला आयोजित

संवाददाता

आगरा। पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बैठक कक्ष में सेवा प्रदाताओं की अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में पीएसआई इंडिया और केनव्यू के सहयोग से जनपद में चलाये जा रहे 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम को सफल बनाने में सेवा प्रदाताओं (स्टाफ नर्स) की भूमिका पर गहन चर्चा हुई। अभिमुखीकरण का मुख्य उद्देश्य डायरिया के बारे में समुदाय को विस्तार से जानकारी देना, ओआरएस और जिंक से डायरिया रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी देना और चिकित्सक के पास जाने की सलाह देना था। कार्यशाला में पीएसआई इंडिया के पंकज कुमार ने बताया कि 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 13 और बिहार के तीन जनपदों में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शून्य से पांच साल तक के बच्चों की डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को शून्य करना और दस्त प्रबंधन को बढ़ावा देना है। डायरिया से किसी भी बच्चे की मौत न होने पाए, इसमें स्टाफ नर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। अभिमुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता डॉ. रिशी गोपाल ने की। उन्होंने डायरिया के बारे में स्टाफ नर्सों का अभिमुखीकरण करते हुए कहा कि डायरिया से बचाव के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। इसलिए अपने घर और आस-पास साफ-सफाई का पूरा ख्याल रखें। बच्चों को कुछ भी खिलाने-पिलाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन-पानी से अवश्य धुल लें। उन्होंने 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम को सफल बनाने में हरसम्भव सहयोग का आश्वासन दिया। इस मौके पर शहरी स्वास्थ्य समन्वयक आकाश गौतम ने डायरिया पर पीएसआई इंडिया द्वारा कराई जा रही अभिमुखीकरण कार्यशाला की सराहना की एवं आश्वासन दिया कि आगे भी इस तरह के आयोजन में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही यह भी कहा कि लोग अपने घरों में ओआरएस एवं जिंक जरूर रखें क अभिमुखीकरण कार्यशाला में सोमचंद्र, रक्षा, पीएसआई इंडिया से आरती और स्टाफ नर्स उपस्थित रहे।

जीएसटी उपायुक्त प्रशांत सिंह के इस्तीफे की जांच करेंगे अपर आयुक्त अयोध्या, शासन को जल्द भेजी जाएगी रिपोर्ट

लखनऊ। अयोध्या में तैनात राज्य कर विभाग के उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह के इस्तीफा देने के प्रकरण में विभागीय जांच तेज कर दी गई है। आयुक्त नितिन बंसल ने अपर आयुक्त अयोध्या संतोष कुमार को जांच सौंपते हुए रिपोर्ट जल्द से जल्द दिए जाने के निर्देश दे दिए हैं। जगदगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में दो दिन पहले प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा था, जिसे संज्ञान में लेते हुए राज्य कर की प्रमुख सचिव कामिनी चौहान रतन ने आयुक्त बंसल को पूरे प्रकरण की जांच कराते हुए रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। आयुक्त ने अयोध्या में तैनात अपर आयुक्त को जांच की जिम्मेदारी देने के साथ ही रिपोर्ट जल्द से जल्द मांगी है।

जमीन अधिग्रहण को लेकर अडानी ग्रुप के अधिकारियों और स्थानीय किसानों के बीच जमकर बवाल

संवाददाता

सरोजनीनगर, लखनऊ। गुरुवार को सरोजनी नगर क्षेत्र में लखनऊ एयरपोर्ट के समीप जमीन अधिग्रहण को लेकर अडानी ग्रुप के अधिकारियों और स्थानीय किसानों के बीच जमकर बवाल हो गया। मामला एयरपोर्ट वीआईपी तिराहे के पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नए पेट्रोल पंप के बगल स्थित खाली पड़ी जमीन का है, जहां बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए की जा रही खुदाई का किसानों ने विरोध किया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों में हाथापाई और तीखी नोकझोंक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरुवार को अडानी ग्रुप के अधिकारी जेसीबी मशीन और मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन की खुदाई शुरू कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही चिल्लावां गांव के किसान बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और काम का विरोध करने लगे। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, जिसके बाद किसानों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल काम रुकवाया। अधिग्रहण का विरोध कर रहे मोहम्मद तौफीक और बुजुर्ग महिला हफीजुल निशा ने बताया कि खसरा संख्या 839, रकबा लगभग 27 बिस्वा जमीन उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। उन्होंने बताया कि उक्त जमीन उनके परिवार के कई सदस्यों के नाम दर्ज है, जिसकी खतौनी भी उनके पास मौजूद है। किसानों का आरोप है कि अडानी के लोग बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक उनकी जमीन पर पहुंचे और जेसीबी से जबरन खुदाई शुरू कर दी। विरोध करने पर उन्हें हटाने की कोशिश की गई। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में अडानी पक्ष जमीन से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोप है कि पुलिस के वापस जाते ही फिर से खुदाई शुरू कर दी गई, जिससे दिनभर तनाव की स्थिति बनी रही। पीड़ितों के अनुसार यह क्रम दिन में चार बार दोहराया गया और हर बार डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाना पड़ा।

फिलहाल पुलिस ने काम पूरी तरह से रुकवा दिया है, लेकिन मौके पर दोनों पक्ष मौजूद हैं और तनाव का माहौल बना हुआ है।

यूजीसी बिल के विरोध में ब्राह्मण परिवार का जोरदार प्रदर्शन, काला कानून वापस लेने की मांग

संवाददाता

लखनऊ। भारत सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी बिल के विरोध में गुरुवार को ब्राह्मण परिवार संगठन के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित जीपीओ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में ब्राह्मण परिवार सहित सवर्ण समाज के सैकड़ों लोग, विशेषकर बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु पांडेय ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो सरकार स्वयं को हिंदू समाज की प्रतिनिधि बताती थी, वही आज समाज को विभाजित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सवर्ण समाज ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर वोट दिया, लेकिन आज उसी का दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है। पांडेय ने चेतावनी दी कि यदि यह 'काला बिल' शीघ्र वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज करते हुए जंतर-मंतर, दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। ब्राह्मण परिवार संगठन के प्रवक्ता अभिषेक अग्निहोत्री ने कहा कि यूजीसी संशोधन को लेकर सवर्ण समाज में गहरा आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार के निर्णयों से उच्च शिक्षा के संस्थानों—सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों—में जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि 21वीं सदी में किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर अपराधी ठहराना किस प्रकार न्यायसंगत है। प्रदेश अध्यक्ष श्याम नारायण मिश्रा ने कहा कि यदि भाजपा यह समझती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो यह उसकी बड़ी भूल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी राजनीतिक दल इस कानून के समर्थन में खड़ा होगा, सवर्ण समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ी तो सवर्ण समाज अपना राजनीतिक विकल्प स्वयं तैयार करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यूजीसी 2026 कानून में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं है और इसे पूरी तरह वापस लेना होगा, अन्यथा आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान संगठन की ओर से प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक मांग-पत्र भी सौंपा गया।

यथावत रहेगा नोएडा, नहीं बनेगा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन,

घर के बाहर से विक्रम टैक्सी चोरी करने वाला युवक गिरफ्तार

संवाददाता

सरोजनीनगर, लखनऊ। बिजनौर पुलिस ने बीते दिनों घर के बाहर से चोरी हुई विक्रम टैक्सी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने उससे विक्रम बरामद कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। बिजनौर पुलिस के मुताबिक औरंगाबाद जागीर की रहने वाली महिला रुबीना कुरैशी ने बीती 27 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर के बाहर खड़ी उसकी विक्रम टैक्सी (यूपी 32 एसएन 5939) चोरी हो गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर टीम गठित की गई और मुखबिर व अन्य साक्ष्यों के जरिए घटना अंजाम देने वाले का पता लगाया जा रहा था। तभी बुधवार शाम करीब 8:15 बजे मुखबिर से पता चला कि घटना अंजाम देने वाला युवक थाना क्षेत्र के रसूलपुर इठुरिया की तरफ जाने वाली रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना गेट नंबर-2 के पास मौजूद है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने उसे मौके से धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बिजनौर कस्बा के कटरा मोहल्ला में रहने वाला मोहम्मद इसराइल बताया। पुलिस ने उसके पास से चोरी की विक्रम वाहन बरामद कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गुरुवार को जेल भेज दिया है।

वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार सिंह का निधन

पत्रकार जगत में शोक की लहर

संवाददाता

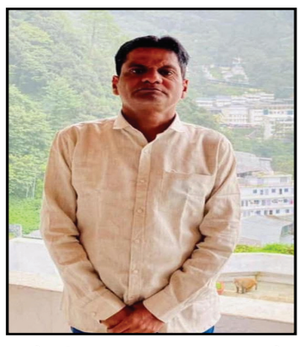

सरोजनीनगर, लखनऊ। सरोजनीनगर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार सुशील सिंह का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पत्रकारिता जगत में गहरा शोक व्याप्त है। मूल रूप से उन्नाव जनपद के हसनगंज निवासी सुशील कुमार सिंह वर्तमान में सरोजनीनगर क्षेत्र में रह रहे थे। वे लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे और अपनी निष्पक्ष, निर्भीक एवं जिम्मेदार लेखनी के लिए पहचाने जाते थे। सरोजनीनगर प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने संगठन को मजबूती प्रदान की और पत्रकारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उनके निधन पर पत्रकार संगठनों, सामाजिक कार्यकताओं एवं शुभचिंतकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैबिनेट ने नहीं जताई सहमति

संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) को यथावत बनाए रखने का ही निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 के तहत नोएडा को मेट्रोपालिटन कारपोरेशन बनाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं प्रदान की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान 22 नवंबर 2023 को नोएडा प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार की जांच एसआइटी से कराने का आदेश दिया था। सरकार ने तीन सदस्यीय एसआइटी गठित कर भ्रष्टाचार की जांच कराई थी। एसआइटी में राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मेरठ के मंडलायुक्त और अपर पुलिस महानिदेशक को शामिल किया गया था। एसआइटी ने नोएडा प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के 12 मामलों की जांच की थी। एसआइटी की 31 अक्टूबर 2023 को शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि नोएडा प्राधिकरण ने अपात्र कास्तकारों को 89.31 करोड़ रुपये का भुगतान नियमों के विपरीत किया था। इसके बाद एसआइटी ने नोएडा प्राधिकरण में पिछले 15 वर्षों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों की भी जांच की थी। इस जांच में भूमि अधिग्रहण के 20 मामलों में 117.56 करोड़ रुपये का भुगतान गलत तरीके से किए जाने का मामला उजागर हुआ था। इसे लेकर एसआइटी ने अपनी रिपोर्ट में नोएडा में मेट्रोपालिटन कारपोरेशन के गठन का सुझाव दिया था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को नोएडा प्राधिकरण में भ्रष्टाचार रोकने व कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए एसआइटी की रिपोर्ट को मुख्य सचिव को देने का आदेश दिया था। औद्योगिक विकास विभाग ने एसआइटी की रिपोर्ट पर संबंधित विभागों का अभिमत लेकर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में नोएडा को मेट्रोपालिटन कारपोरेशन बनाने के संबंध में प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद कैबिनेट ने कारपोरेशन न बनाकर नोएडा को यथावत बनाए रखने का निर्णय किया है। यह भी पढ़ें- गोरखपुर को 721.40 करोड़ की सीवरेज परियोजना की मिली मंजूरी, 17 वार्डों के 1.95 लाख लोगों को होगा फायदा इस संदर्भ में संबंधित विभागों ने यह तर्क दिया कि यदि किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगर के रूप में अधिसूचित किया गया है तो उस क्षेत्र में कोई मेट्रोपालिटन कारपोरेशन गठित नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा है कि मेट्रोपालिटन कारपोरेशन बनने से औद्योगिक निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी प्रदीप अवस्थी द्वारा अमृतशील प्रिंटिंग प्रेस, ए. एस. पब्लिक कॉलेज, भवन संख्या-2 अमृतशील नगर रायबरेली रोड लखनऊ उ. प्र. से मुद्रित कराकर कार्यालय विविध सन्देश सी-1437/3 इंदिरा नगर लखनऊ उ. प्र. से प्रकाशित,
संपादक : प्रदीप अवस्थी RNI NO:- UPHIN/2011/41620 नोट : सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ स्थित न्यायालय होगा E-mail-vividhsandesh123@gmail.com सम्पर्क :- 9838799599, 7080510556

संक्षेप

अज्ञात वाहन ने कार में मारी टक्कर तीन घायल

संवाददाता

उन्नाव। मौरावा रोड पर घने कोहरेऔर तेज स्पीड का दिखा कहर, कार को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे कार चालक समेत अन्य लोग घायल हो गये।टक्कर मारने वाला वाहन सहित फरार हो गया।राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस द्वारा घायलों को सीएचसी भेजा गया। घायलों को मामूली चोंटे ही आईं जबकि उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आज बृहस्पतिवार को प्रातः लगभग समय सात बजे पुरवा-मौरावां मार्ग पर मौरावां की ओर जा रही कार ने जैसे ही मिहीखेड़ा गांव को पार किया था तभी सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे कार के परखच्चे उड़ गये।लेकिन एअर बैग खुलने से कार चालक व अन्य दो सवारों को मामूली चोंटे आईं।राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरवा पहुंचाया जहां घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।कार सवार दिल्ली से चलकर जनपद रायबरेली की तहसील महराजगंज के नैनिया गांव निवासी अपने मौसा रामस्वरुप के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे।घायलों में दो सगे भाइयों में धर्मराज 30 व सहदेव 28, पुत्रगण राजाराम एवं उनकी बहन लवली पत्नी दिनेश निवासी गांव पानकुवरखेडा शिवगढ़ भी साथ में थी।सुबह घना कोहरा होने के कारण सामने से वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्ष दर्शियों के कहने के अनुसार ओवर स्पीड होने के कारण यह एक्सीडेंट हुआ हैं

दिल्ली से रोडवेज बस द्वारा घर लौट रहे चालक को जहर खुरानी गिरोह ने बनाया शिकार

संवाददाता

बांगरमऊ, उन्नाव। दिल्ली से रोडवेज बस द्वारा घर लौट रहे एक ड्राइवर को जहरखुरानी गिरोह ने शिकार बना डाला।गिरोह के सदस्यों में ड्राइवर की नगदी, फोन पार कर दिया। बस चालक उसे बेहोशी के हालात में छोड़ कर चला गया।स्थानीय लोगों उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसे रेफर कर दिया गया।

क्षेत्र के ग्राम गहिरा निवासी 25 वर्षीय अमित पुत्र राजेश दिल्ली में रहकर निजी वाहन चालक के रूप में नौकरी करता है। बुधवार की शाम वह परिवहन विभाग की बस में सवार होकर घर लौट रहा था। रास्ते में जहर खुरानी गिरोह ने किसी तरह उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके पास से नगदी, मोबाइल फोन व ड्राइवरी लाइसेंस आदि पार कर दिया। आज गुरुवार की सुबह बस परिचालक ने उसे बेहोशी की हालत में नगर के नानामऊ तिराहे पर फेंक दिया। स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे यहां के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।जहां से डाक्टरों ने उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

ग्राम प्रधान द्वारा विशाल स्वास्थ्य मेले का किया गया आयोजन, सैकड़ों ग्रामीणों ने लिया लाभ

संवाददाता

गंजमुरादाबाद, उन्नाव। जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां की पड़ोसी ग्राम पंचायत गंजजलालाबाद में ग्राम प्रधान अभिषेक दीक्षित के नेतृत्व में आज एक दिवसीय विशाल स्वास्थ्य मेले, निशुल्क दवा वितरण एवं नेत्र परीक्षण शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने पहुँचकर अपनी सेहत की जाँच कराई और विशेषज्ञों से परामर्श लिया।

स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन बांगरमऊ के भाजपा विधायक श्रीकांत कटियार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना और लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करना ही इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने जोर दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अक्सर इलाज के अभाव में बीमारियों से जूझते रहते हैं, ऐसे शिविर उनके लिए वरदान साबित होते हैं। शिविर में जिले के प्रतिष्ठित अस्पतालों के अनुभवी डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। इस शिविर में बुखार, जुकाम और अन्य मौसमी बीमारियों की जाँच के साथ ही नेत्र परीक्षण मोतियाबिंद और दृष्टि दोष की जाँच कर उचित परामर्श दिया गया। जाँच के उपरांत मरीजों को आवश्यक दवाएं मुफ्त में वितरित की गईं।शिविर में ब्लड प्रेशर और मधुमेह के मरीजों के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए थे। स्वास्थ्य मेले को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही पंजीकरण काउंटर पर लंबी कतारें लग गई थीं। नेत्र परीक्षण के दौरान जिन लोगों को चश्मे या आगे के इलाज की आवश्यकता थी, उन्हें संबंधित संस्थानों के लिए रेफर भी किया गया।

कार्यक्रम के समापन पर ग्राम प्रधान अभिषेक दीक्षित ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया।उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को बैग भी वितरित किये गए। इस दौरान प्रमुख समाजसेवी व राष्ट्रीय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश दीक्षित एडवोकेट, संतोष शुक्ला, चौधरी प्रमेश सिंह, पप्पू त्रिवेदी, नगर पंचायत गंजमुरादाबाद के पूर्व अध्यक्ष रामनरेश कुशवाहा, सुनील दीक्षित प्रधान प्रतिनिधि स्पर्श दीक्षित, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव बड़े ही धूम-धाम से मनाया गया

संवाददाता

हमीरपुर ।महेरा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।इस मौके पर विद्यालय में पढ़ने बाले बच्चों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। वही कार्यकम में सफल हुए छात्रो को पुरुस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुस्करा विकास खंड क्षेत्र के महेरा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव कार्यक्रम मनाया गया इस अवसर पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में आये मुस्करा ब्लाक प्रमुख वीरनारायण राजपूत ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पूजा अर्चना कर शुरूआत कराई , उसके बाद उमेश कुमार ब्लॉक व्यायाम शिक्षक व अनिल कुमार अनुदेशक के देखरेख में बालक बालिकाओं को लेकर खेल उत्सव के अंतर्गत 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ की दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें बालक वर्ग में सतीश ने प्रथम स्थान नीरज द्वितीय स्थान हासिल किया अनीश तृतीय स्थान पर रहे वही बालिका वर्ग में खुशी देवी प्रथम स्थान, प्रिया द्वितीय स्थान व सृष्टि ने तृतीय स्थान पर रही वही विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुखदेव की अध्यक्षता में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे बच्चों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।उनके साथ पूर्व अध्यक्ष शब्बीर खान व विशिष्ट अतिथि अजयपाल राजपूत प्रबंधक श्री पीएनबी इंटर कॉलेज चिल्ली व लखन राजपूत आयरन स्टोर मुस्करा व अरविंद सिंह राजपूत समाज सेवी आदि उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना स्वागत गीत के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या,दहेज प्रथा, देशभक्ति नाटक,गीत व नृत्य प्रस्तुत किये गए। जिसमे अभिभावकों गणमान्य नागरिकों का मन मोह लिया विद्यालय के प्रभारी प्रधान अध्यापक बाबूराम चक्रवर्ती ने बताया कि बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसमें कक्षा शिक्षण के साथ-साथ पाठ्य सहगामी गतिविधियां जैसे खेलकूद, विज्ञान की प्रतियोगिताएं,लेखन ,गायन ,वाद विवाद, आदि सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चों के अंदर विशिष्ट क्षमताओं को उनके ज्ञान में एक सकारात्मक परिणाम देता है। इसके उपरांत प्रतिभागी छात्राओं को विशिष्ट अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया जिसमें शिक्षक राजकुमार, अमर सिंह, विनोद कुमार, बृजेंद्र कुमार, करनसिंह, मुकेश कुमार ने व्यवस्थाएं बनाई रखी साथ ही सत्येंद्र यादव ,सुजीत कुमार, अजय कुमार, देवेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में विशेष सहयोग किया। नागरिकों व अभिभावकों में कार्यक्रम की सराहना की, मंच का संचालन जीतेन्द्रसिंह व शिव शंकर विश्वकर्मा शिक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

तेज रफ्तार डीसीएम ने ई रिक्शा में मारी टक्कर तीन घायल

संवाददाता

बांगरमऊ, उन्नाव। कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक सड़क हादसे में ई-रिक्शा सवार दो महिलाओं और चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक तेज रफ्तार डीसीएम ने पीछे से ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद डीसीएम चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।

टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा पर सवार दोनों महिला यात्री लगभग 30 मीटर दूर खंती में जा गिरीं, जबकि ई-रिक्शा चालक वाहन के नीचे दब गया। आसपास मौजूद लोगों ने चीख-पुकार सुनकर घायलों को बाहर निकाला और निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान नसीरपुर भीखन गांव निवासी ई-रिक्शा चालक ज्ञानचंद्र (40) पुत्र लज्जाराम, और ई-रिक्शा में सवार मीरापाल (55) पत्नी बृजकिशोर तथा रामश्री (65) पत्नी निरंजन के रूप में हुई है। ये सभी नसीरपुर भीखन गांव के ही रहने वाले हैं।

प्रारंभिक उपचार के लिए घायलों को सीएचसी बांगरमऊ ले जाया गया। वहां से रामश्री और मीरापाल को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है, जबकि चालक ज्ञानचंद्र को जिला अस्पताल रेफर किया गया। दोनों महिलाओं की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

यह हादसा स्लाइस स्पाइस होटल के सामने हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन

संवाददाता

हसनगंज, उन्नाव।कस्बा में स्थित संतोषी माता मंदिर के परिसर में यूजीसी कानून के विरोध में बृहस्पतिवार को सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया।प्रदर्शनकारियों ने संतोषी माता मंदिर परिसर से पैदल मार्च निकालते हुए एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

हसनगंज कस्बे के बाहर स्थित संतोषी माता मंदिर से दोपहर बृहस्पतिवार 12 बजे क्षत्रिय महासभा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग एकत्र हुए। इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शनकारी तहसील पहुंचे, जहां एसडीएम प्रज्ञा पाण्डेय को सात सूत्रीय राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।

इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया यूजीसी कानून समाज के हितों के खिलाफ है और इसे जबरन थोपा जा रहा है।उन्होंने मांग की कि इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा।प्रदर्शन में प्रमुख रूप से बृजेंद्र सिंह, डॉ. भानु प्रताप सिंह, आशीष मिश्र अन्नू, राकेश सिंह, ओम जी तिवारी, नवीन सिंह, मिलन पाण्डेय, अरुण दीक्षित, बिपिन सिंह, अजीत, विकास, राजन शर्मा, कामेश दीक्षित और आनंद पंडित मौजूद रहे।

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर की आत्म हत्या

संवाददाता

बांगरमऊ, उन्नाव। अज्ञात कारणों के चलते युवक अपने घर में फांसी के फंदे पर झूल गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

नगर के स्टेशन रोड निवासी 22 वर्षीय अभिषेक त्रिवेदी पुत्र सुरेश ने अपने घर में बने जाल में धोती से फंदा बनाकर उसमें लटककर मौत को गले लगा लिया। जब परिजनों को पता चला तो कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है। घटना से मृतक का भाई विवेक, बहन प्रियंका, माँ पूनम सहित सभी परिजन रोकर बेहाल है। कोतवाल अखिलेश चंद पांडेय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। मृतक का परिवार मूल रूप से बेहटा मुजावर थानाक्षेत्र के नौशहरा अरगूपुर का निवासी है। किंतु लंबे समय से नगर में घर बनाकर रह रहा है।

कार सवार दबंगो ने बस के चालक व परिचालक के साथ की मारपीट

संवाददाता

बांगरमऊ, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बुधवार और गुरुवार की मध्यरात्रि लगभग एक बजे बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र की हवाई पट्टी के पास कार सवार आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक बस को रोककर उसके ड्राइवर और कंडक्टर पर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, लखनऊ से दिल्ली जा रही बस को लखनऊ में दो सवारियों का इंतजार करने के लिए कहा गया था, जिसमें ड्राइवर ने 10 मिनट का समय लिया। इससे नाराज कार सवार दबंगों ने बस का 100 किलोमीटर तक पीछा किया। किलोमीटर संख्या 241 पर हवाई पट्टी के पास उन्होंने बस के आगे अपनी कार लगा दी और उतरकर ड्राइवर-कंडक्टर पर लकड़ी की पट्टियों से हमला कर दिया। बस में बैठे एक यात्री ने घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया, जिस पर दबंग उस पर भी हावी हो गए। इस मारपीट में बागपत जिले के शुरूर पुर कला गांव निवासी ड्राइवर बबलू (48) और इटावा जिले के बेरौडी निवासी कंडक्टर राजेश (40) को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर यूपीडा टीम मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी बांगरमऊ में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस घटना से एक्सप्रेसवे पर गश्त करने वाली पुलिस टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि हमलावर आधे घंटे तक बस में तोड़फोड़ और मारपीट करते रहे, लेकिन इस दौरान एक्सप्रेसवे पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। सूचना मिलने के बाद डायल 112 पुलिस ने मौके से फरार हुए कार सवार सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मुन्ना कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।

एसडीएम ने निर्मित सीसी मार्ग एवं नाली का किया निरीक्षण

संवाददाता

बांगरमऊ, उन्नाव। उप जिलाधिकारी बृजमोहन शुक्ला ने आज नगर पालिका प्रशासन द्वारा निर्मित सीसी मार्ग एवं नाली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, उपयोग की गई सामग्री और मानकों का बारीकी से जायजा लिया। मौके पर नाली के प्लास्टर में खामियां पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। गौरतलब है कि करीब 1 माह पूर्व नगर के सराय रोड से नानामऊ मार्ग को जोड़ने वाले रास्ते पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा सीसी मार्ग एवं नाली का निर्माण कराया गया है। इसी सीसी मार्ग का आज उपजिलाधिकारी बृजमोहन शुक्ला ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि नालियों का दुरुस्त होना अत्यंत आवश्यक है। ताकि जलभराव की समस्या न उत्पन्न हो और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने नाली के प्लास्टर को मानक के अनुरूप मजबूत और समतल कराने के साथ-साथ सीसी मार्ग की फिनिशिंग पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका के लिपिक रविन्द्र बाबू एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। एसडीएम ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण कराने, गुणवत्ता से कोई समझौता न करने तथा भविष्य में इस प्रकार की कमियां न पाए जाने की हिदायत दी। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय नागरिकों ने निरीक्षण को सकारात्मक कदम बताते हुए उम्मीद जताई कि सुधार कार्य शीघ्र पूरा होगा और क्षेत्र में आवागमन व जलनिकासी की व्यवस्था बेहतर होगी।

कथित प्रेम प्रसंग धमकी व पैसों की मांग से आहत युवक ने की आत्महत्या

संवाददाता

उन्नाव। कथित प्रेम प्रसंग, धमकी और पैसों की मांग से आहत होकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कोतवाली सदर थाना क्षेत्र के अकरमपुर निवासी 23 वर्षीय ललित कश्यप के रूप में हुई है। परिजनों ने प्रेमिका के पिता पर उत्पीड़न और 12 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है।परिजनों के अनुसार, ललित वर्ष 2023 से मगरवारा निवासी एक युवती के संपर्क में था और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। इसी बात से नाराज होकर युवती के पिता ने ललित के खिलाफ कथित तौर पर साजिश रचनी शुरू कर दी। आरोप है कि युवती के पिता ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ललित को थाने में बंद करा दिया, जहां उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बताया गया कि थाने में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता कराया गया, जिसके बाद ललित को छोड़ा गया। हालांकि, परिजनों का आरोप है कि समझौते के बाद भी उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ। युवती के पिता ने कथित तौर पर ललित को रास्ते में रोककर धमकाया और उस पर 12 लाख रुपये देने का दबाव बनाया। रकम न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी गई।इस लगातार मानसिक दबाव और भय से ललित पूरी तरह टूट गया था। परिजनों ने बताया कि वह कई दिनों से परेशान था, चुप-चुप रहने लगा था और किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रहा था।प्रताड़ना से आहत होकर ललित ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।ललित अपने परिवार का इकलौता बेटा और दो बहनों का अकेला भाई था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं बहनों का सहारा छिन गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।परिजनों ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की होती तो आज ललित जिंदा होता। फिलहाल, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

किसान यूनियन का प्रदर्शन

संवाददाता

शाहजहांपुर , भारतीय किसान यूनियन परिवर्तनवादी ने खिरनीबाग रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूनियन ने स्वास्थ्य विभाग में हुए 1.20 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में दोषियों पर तत्काल कार्रवाई और जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बाद भी सुविधाओं के अभाव को लेकर अपनी मांगें रखी हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपये का घोटाला यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जनपद के स्वास्थ्य विभाग में 1 करोड़ 20 लाख रुपये का घोटाला हुआ था। इस मामले में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की जांच में दोषी पाए गए थे, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने घोटालेबाजों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी बताया कि जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज तो बना दिया गया है, लेकिन वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इस अस्पताल पर जनपद ही नहीं, बल्कि गैर-जनपदों के लोग भी निर्भर थे, जिन्हें अब असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन ने इसे पुनः जिला अस्पताल बनाने की मांग की है। परेशानी को रोकने की मांग की इसके अतिरिक्त, किसानों ने ददरौल स्थित के.आर. पेपर मिल से निकलने वाले प्रदूषण और धुएं से ग्रामीणों को हो रही परेशानी को रोकने की मांग की। उन्होंने न्यायालय के आदेशों के बावजूद जमीनों पर हो रहे कब्जों को समाप्त करने, जनपद में आवारा पशुओं के आतंक पर रोक लगाने और अवैध टोल नाकों के संचालन को बंद करने सहित कई अन्य समस्याओं के समाधान की भी मांग की। भारतीय किसान यूनियन परिवर्तनवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर, यह धरना जिला अध्यक्ष मुकुट बिहारी के नेतृत्व में शुरू किया गया है।

बच्चों के सामने पत्नी ने पति का गला काटा

प्रेमी संग मिलकर हत्या की; शाहजहांपुर में बेटा बोला- 3 अंकल आए, पापा को मार डाला

संवाददाता

शाहजहांपुर , पत्नी ने मासूम बच्चों के सामने चाकू से अपने पति का गला काट डाला। महिला ने अपने प्रेमी और उसके दो साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद कई घंटे बाद तक कमरे में शव के पास ही बैठी रही। सुबह मजदूरी पर साथ ले जाने के लिए देवर ने दरवाजा खटखटाया तो रोने-बिलखने का नाटक करने लगी। देवर घर के अंदर पहुंचा तो हालात देखकर चौंक गया। बड़े भाई का शव चारपाई पर पड़ा था। गर्दन कटी हुई थी। फर्श पर खून ही खून फैला था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पत्नी को हिरासत में लिया। पुलिस से पूछताछ के दौरान 5 साल के मासूम बेटे ने बताया- रात में 3 लोग आए थे, मम्मी के साथ मिलकर पापा का गला काट दिया। फिर अंकल चले गए। हम लोगों को भी चाकू दिखाकर डराया। देवर ने बताया- भाभी का दो साल से अपने ही सगे भांजे से अफेयर चल रहा था। आए दिन पति-पत्नी में विवाद होता था। 8 महीने पहले गांव और परिवार के लोगों ने सुलह कराया था। पर भाभी नहीं सुधरी। 3 महीने पहले घर से भाग गई थी। कुछ दिन पहले ही लौटी थी और अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे भाई को मार डाला। भाई ने बताया- मैंने रात 1 बजे भाई के चीखने की आवाज सुनी थी और भाभी के भांजे समेत 3 लोगों को घर से भागते हुए देखा था। भाई ने हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर पुवायां थाना क्षेत्र की है।पुवायां थाना क्षेत्र के बटपुरा चंदू गांव निवासी बलराम (30) की 12 साल पहले पूजा (27) से शादी हुई थी। बलराम के छोटे भाई राजू ने बताया- बुधवार रात मैं और भाई बलराम गांव में भागवत सुनने गए थे। वहां से मैं अपने घर चला गया और भाई अपने। हम दोनों के घर सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर हैं। रात करीब एक बजे मैंने भाई की चीख सुनी। झांककर देखा तो भांजा आदेश और दो और युवक मकान से निकल रहे थे। भांजा होने के चलते मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। विकलांग होने के कारण मैं आगे तक नहीं जा पाया, इसलिए दो अन्य लोगों को पहचान नहीं पाया। आज सुबह करीब 6:30 बजे मजदूरी पर जाने के लिए मैं भाई के घर पहुंचा और आवाज लगाई। भाभी पूजा रोते-बिलखते हुए बाहर आई पर कुछ नहीं बोला। मैं घर के अंदर गया तो लाश देखकर चीख पड़ा। पूछने पर भाभी ने कहा- खुद ही गला काट लिया। सूचना पर एएसपी दीक्षा भंवरे अरुण समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर को सील कर खून के निशान, हथियार और अन्य सबूत जुटाए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। राजू ने कहा- भाभी पूजा ने ही अपने भांजे आदेश और साथियों ने ही मिलकर मेरे भाई की हत्या की है, क्योंकि बलराम अपनी पत्नी पूजा के अवैध संबंधों को लेकर रोक-टोक करता था।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शाहजहांपुर में प्रदर्शन

संवाददाता

शाहजहांपुर , महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने खिरनीबाग रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कम मानदेय, उत्पीड़न और सेवा समाप्ति की धमकियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें अक्सर मानदेय रोकने, काटने और सेवा समाप्ति की धमकी दी जाती है। उनका कहना है कि 6,000 रुपये के मानदेय में परिवार चलाना और बच्चों को शिक्षा दिलाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा, कई वर्षों से मोबाइल रिचार्ज का खर्च भी उन्हें स्वयं उठाना पड़ रहा है, जिस पर विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी मुख्य मांग है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अन्य राज्यों की तरह मानदेय में वृद्धि की जाए। साथ ही, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त धनराशि की व्यवस्था की जाए। कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए बेसिक और माध्यमिक स्कूलों की तरह ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश की भी मांग की। उन्होंने बाल विकास योजना का विस्तार कर पूरी आबादी को कवर करने और बढ़ती आबादी को देखते हुए नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की बात कही। अन्य मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भुगतान की जानकारी के लिए पासबुक बनवाना और अतिरिक्त केंद्र का प्रभार संभालने वाली तथा संगिनी व मॉनिटर का कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय देना शामिल है। पदाधिकारियों ने प्रशासन को 18 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है और चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।

कोतवाली के नवनिर्मित गेट का पुलिस अधीक्षक ने किया उद्घाटन

संवाददाता

बांगरमऊ, उन्नाव। कोतवाली के नवनिर्मित गेट का पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर व शिलापट खोलकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पुलिस अधीक्षक में अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाली में प्रवेश हेतु एक भव्य गेट का निर्माण कराया गया है। नवनिर्मित मुख्य द्वार का आज गुरुवार को पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंहने फीता काटकर व शिलापट खोलकर उद्घाटन किया। इस दौरान एडिशनल अखिलेश सिंह, सीओ संतोष सिंह ,कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडेय आदि सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद कप्तान ने बेहतर पुलिसिंग के गुर बताते हुए अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ितो के साथ त्वरित न्याय हेतु पुलिस को तैयार रहने की हिदायत दी।